



Exam Genius

India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK RAILWAY Exam



BANKING AND FINANCIAL AWARENESS

5 - 11 OCTOBER

2ND WEEK OF OCTOBER

50+ MCQ
with detailed
explanation



- Banking & finance
- Banking Facilities
- Banking Appointment
- Banking Agreement



Ques: Which insurance company signed a bancassurance agreement with Equitas Small Finance Bank to expand insurance access?

किस इश्योरेंस कंपनी ने Equitas Small Finance Bank के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बीमा पहुंच बढ़ाने के लिए बैंकअस्सुरेंस समझौता किया?

- A. ICICI Lombard / ICICI लोम्बार्ड
- B. HDFC ERGO / HDFC ईआरजीओ
- C. TATA AIG General Insurance / TATA AIG जनरल इश्योरेंस
- D. SBI General Insurance / SBI जनरल इश्योरेंस
- E. Reliance General Insurance / रिलायंस जनरल इश्योरेंस

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- TATA AIG General Insurance Company signed a bancassurance agreement with Equitas Small Finance Bank (SFB) to expand insurance access across rural and urban areas.
- TATA AIG जनरल इश्योरेंस कंपनी ने Equitas Small Finance Bank (SFB) के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बीमा पहुंच बढ़ाने के लिए बैंकअस्सुरेंस समझौता किया।
- The tie-up aims to strengthen financial protection for households and small businesses in emerging India markets.
- इस साझेदारी का उद्देश्य उभरते भारत के बाजारों में घरों और छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करना है।

About Equitas Small Finance Bank :

- Established : 2016
 - HQ : Chennai, Tamil Nadu
 - MD & CEO : Vasudevan P N
 - Tagline : It's Fun Banking
-

Ques : According to the World Gold Council (WGC), what is India's global rank as an investor in gold ETFs in 2025?

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) के अनुसार, 2025 में भारत का गोल्ड ईटीएफ निवेशकों में वैश्विक स्थान कौनसा है-?

- A. 5th
- B. 6th
- C. 7th
- D. 8th
- E. 9th

Answer : Option c

Explanation | व्याख्या:

- As per the World Gold Council (WGC), India ranked 7th globally among nations investing in gold ETFs as of September 26, 2025.
 - वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) के अनुसार, भारत 26 सितंबर 2025 तक वैश्विक स्तर पर 7वें स्थान पर रहा।
 - The US led with AUM of \$231.5 billion, followed by UK, Switzerland, Germany, China, and France.
 - अमेरिका शीर्ष पर रहा (\$231.5 अरब), इसके बाद यूके, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, चीन और फ्रांस का स्थान रहा।
 - India's AUM stood at \$8.9 billion, equal to Canada, indicating growing interest among Indian investors amid global price volatility and economic uncertainty.
 - भारत का AUM \$8.9 अरब रहा, जो कनाडा के बराबर है, जिससे वैश्विक मूल्य अस्थिरता और आर्थिक अनिश्चितता के बीच भारतीय निवेशकों की बढ़ती रुचि दिखाई देती है।
-

Ques : According to the Asian Development Bank (ADB), what is India's GDP growth forecast for FY26?

एशियाई विकास बैंक (ADB) के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना है?

- A. 6.2%
- B. 6.5%
- C. 6.7%
- D. 7.0%
- E. 7.2%

Answer : Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Asian Development Bank (ADB), in its Asian Development Outlook September 2025 report, has retained India's GDP growth forecast at 6.5% for FY26.
 - एशियाई विकास बैंक (ADB) ने अपनी एशियाई विकास दृष्टिकोण सितंबर 2025 रिपोर्ट में भारत की वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.5% बनाए रखी है।
 - Strong domestic consumption and robust services exports are cited as key growth drivers.
 - मजबूत घरेलू उपभोग और सेवा निर्यात प्रमुख विकास कारक होंगे।
 - Inflation is expected to ease to 3.1% in FY26, but risks remain from global trade tensions and geopolitical uncertainties.
 - मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2026 में 3.1% तक घट सकती है, हालांकि वैश्विक व्यापार तनाव और भूराजनीतिक अनिश्चितताओं से जोखिम ब-ने रहेंगे।
 - The services sector will remain the major driver of growth in FY26 and FY27.
 - सेवा क्षेत्र वित्त वर्ष 2026 और 2027 में विकास का प्रमुख चालक बना रहेगा।
-

Ques: As per the Controller General of Accounts (CGA), what percentage of the full-year fiscal deficit target had the Centre reached by August-end 2025? महालेख नियंत्रक (CGA) के अनुसार, अगस्त 2025 के अंत तक केंद्र अपने वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का कितने प्रतिशत तक पहुंच चुका था?

- A. 25%
- B. 27%
- C. 33%
- D. 38.1%
- E. 40%

Answer :Option D

Explanation | व्याख्या:

- According to the Controller General of Accounts (CGA), India's fiscal deficit reached 38.1% of the full-year target by the end of August 2025.

- महालेख नियंत्रक (CGA) के अनुसार, अगस्त 2025 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा वार्षिक लक्ष्य का 38.1% तक पहुंच गया।
- This was higher compared to the same period of 2024-25, when it was 27% of the Budget Estimates (BE).
- यह 2024-25 की समान अवधि की तुलना में अधिक था, जब यह बजट अनुमान (BE) का 27% था।
- The fiscal deficit in absolute terms stood at ₹5.98 lakh crore during April–August 2025-26.
- सकल रूप में, अप्रैल–अगस्त 2025-26 के दौरान राजकोषीय घाटा ₹5.98 लाख करोड़ रहा।
- Fiscal deficit represents the gap between the government's total revenue and total expenditure.
- राजकोषीय घाटा सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर दर्शाता है।

Ques : According to the new RBI guidelines, what flexibility have lenders received regarding EMI-based floating rate personal loans?

नए आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, ईएमआईआधारित फ्लोटिंग रेट पर्सनल लोन के - संबंध में ऋणदाताओं को क्या लचीलापन मिला है?

- A) Mandatory switch to fixed rate | फिक्स्ड रेट में स्विच अनिवार्य
- B) No option to switch | स्विच का कोई विकल्प नहीं
- C) Discretion to offer switch at reset | रीसेट के समय स्विच देने का अधिकार
- D) Switch allowed only once during loan tenure | लोन अवधि में केवल एक बार स्विच की अनुमति
- E) Borrower must decide at loan sanction | उधारकर्ता को लोन स्वीकृति पर तय करना होगा

Answer | सही उत्तर: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Earlier, RBI made it mandatory for lenders to provide borrowers the option to switch floating rate EMI-based loans to fixed rate at the time of reset.
- पहले, आरबीआई ने ऋणदाताओं के लिए यह अनिवार्य किया था कि वे उधारकर्ताओं को फ्लोटिंग रेट ईएमआईआधारित लोन को रीसेट के समय फिक्स्ड रेट में बदलने का विकल्प -

दें।

- Now, RBI has left it to the discretion of lenders, offering greater flexibility to banks, NBFCs, and housing finance companies.
- अब, आरबीआई ने यह ऋणदाताओं की इच्छा पर छोड़ दिया है, जिससे बैंकों, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को अधिक लचीलापन मिला है।
- Banks can also adjust spread components like operating cost, cost of funds, tenor premium, and profit margin earlier than three years if it benefits borrowers.
- बैंकों को यह अनुमति भी है कि वे यदि उधारकर्ताओं को लाभ होता है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, फंड की लागत, टेन्योर प्रीमियम और प्रॉफिट मार्जिन को तीन साल से पहले समायोजित कर सकें।

Ques: Which bank, in partnership with Freecharge, launched India's first gold-backed credit line on UPI?

किस बैंक ने फ्रीचार्ज के साथ साझेदारी में भारत की पहली सोने समर्थित क्रेडिट लाइन-UPI पर शुरू की?

- A. HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- B. Axis Bank / एक्सिस बैंक
- C. ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- D. Kotak Mahindra Bank / कोटक महिंद्रा बैंक
- E. State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक

Answer : Option B

Explanation / व्याख्या:

- Axis Bank, in partnership with Freecharge, launched India's first gold-backed credit line on UPI.
- एक्सिस बैंक ने फ्रीचार्ज के साथ साझेदारी में भारत की पहली सोने समर्थित क्रेडिट लाइन-UPI पर शुरू की।
- The initiative follows the guidelines of NPCI (National Payments Corporation of India).
- यह पहल NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियानिर्देशों के अनुसार है।-के दिशा (
- The product is aimed at simplifying working capital access, financing for

business growth, and urgent liquidity needs.

- यह उत्पाद कार्यशील पूंजी की आसान पहुंच, व्यवसाय वृद्धि वित्तपोषण और तात्कालिक तरलता जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है।
- It is designed for MSMEs, self-employed individuals, and merchants, enabling them to leverage gold assets for instant, flexible credit.
- यह एमएसएमई, स्वरोजगार करने वालों और व्यापारियों के लिए बनाया गया है, जिससे वे अपने सोने की संपत्तियों का उपयोग तुरंत और लचीले क्रेडिट के लिए कर सकें।

About Axis Bank :

- Established : 1993
- HQ : Mumbai, Maharashtra
- MD & CEO : Amitabh Chaudhary
- Tagline : Badhti Ka naam Zindagi

Ques: RBL Bank has partnered with which organization for a bancassurance agreement?

RBL बैंक ने बैंकएश्योरेंस समझौते के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है?

- A. SBI Life Insurance / एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस
- B. HDFC Life Insurance / एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस
- C. Max Life Insurance / मैक्स लाइफ इंश्योरेंस
- D. Life Insurance Corporation of India (LIC) / भारतीय जीवन बीमा निगम)LIC)
- E. ICICI Prudential Life Insurance / आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस

Answer : Option D

Explanation | व्याख्या:

- RBL Bank entered into a bancassurance partnership with LIC, India's largest life insurer.
- RBL बैंक ने भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम)LIC) के साथ बैंकएश्योरेंस साझेदारी समझौता किया।
- This tie-up enables RBL Bank customers to access the entire range of LIC's life insurance products.

- इस साझेदारी से RBL बैंक के ग्राहक LIC के सभी जीवन बीमा उत्पादों का लाभ उठा सकेंगे।
- Products will be available through RBL Bank's branch network and digital channels.
- ये उत्पाद RBL बैंक की शाखाओं और डिजिटल चैनलों के माध्यम से उपलब्ध होंगे।
- The collaboration aims to boost insurance penetration and offer comprehensive financial solutions.
- यह साझेदारी बीमा कवरेज बढ़ाने और समग्र वित्तीय समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।

Ques : For Q3 FY26 (Oct–Dec 2025), what is the interest rate for the Public Provident Fund (PPF)?

वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही (दिसंबर-अक्टूबर) 2025) के लिए सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) की ब्याज दर क्या है?

- A) 7.5%
- B) 7.7%
- C) 8.2%
- D) 7.1%
- E) 6.9%

Answer : Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Finance Ministry confirmed that for Oct–Dec 2025 (Q3 FY26), the PPF interest rate remains unchanged at 7.1%.
- वित्त मंत्रालय ने पुष्टि की कि अक्टूबर-दिसंबर-2025 (Q3 FY26) के लिए पीपीएफ की ब्याज दर 7.1% अपरिवर्तित रहेगी।
- Other small savings schemes like Sukanya Samriddhi (8.2%), NSC (7.7%), and Kisan Vikas Patra (7.5%) also remain unchanged.
- अन्य छोटी बचत योजनाएं जैसे सुकन्या समृद्धि (8.2%), एनएससी (7.7%), और किसान विकास पत्र (7.5%) भी अपरिवर्तित रहेंगी।
- These schemes are mostly operated by post offices and banks, with both principal and interest guaranteed by the Government of India.
- ये योजनाएं मुख्य रूप से डाकघरों और बैंकों द्वारा संचालित होती हैं और इनमें मूलधन और ब्याज भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत होता है।

**Ques : RBI's "Scheme for Facilitating Accelerated Payout – Inoperative Accounts and Unclaimed Deposits" will be effective for which period?
आरबीआई की "Scheme for Facilitating Accelerated Payout – Inoperative Accounts and Unclaimed Deposits" किस अवधि के लिए लागू होगी?**

- A. April 2025 – March 2026
- B. October 2025 – September 2026
- C. January 2025 – December 2025
- D. July 2025 – June 2026
- E. None of these

Answer : Option B

Explanation | व्याख्या:

- The RBI launched the "Payout Structure" scheme to encourage banks to trace inactive customers and return unclaimed deposits.
- RBI ने "पेवआउट स्ट्रक्चर" योजना शुरू की है ताकि बैंकों को निष्क्रिय खाताधारकों तक पहुँचने और अनक्लेम्ड जमा राशि लौटाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- Duration: October 1, 2025 – September 30, 2026 (one-year scheme).
- अवधि: 1 अक्टूबर 2025 – 30 सितम्बर 2026 (एक वर्ष की योजना)।
- Under the scheme, banks will receive differential payouts based on account inactivity period and deposit amount, which encourages reactivation of dormant accounts.
- इस योजना के तहत, बैंक खाते की निष्क्रिय अवधि और जमा राशि के आधार पर भुगतान प्राप्त करेंगे, जिससे निष्क्रिय खातों को पुनः सक्रिय करने में मदद मिलेगी।

Example of Payout Structure | भुगतान संरचना उदाहरण:

अवधि (Years)	भुगतान प्रतिशत	अधिकतम राशि (Whichever is less)
Up to 4	5% of amount	₹5,000
4–8	6% of amount	₹10,000
8–10	7% of amount	₹15,000
10+ (Unclaimed with DEA Fund)	7.5% of amount	₹25,000

- This **one-year scheme** motivates banks to locate customers, reactivate accounts, and ensure rightful claimants receive their unclaimed deposits.
- यह एक वर्ष की योजना बैंकों को ग्राहकों तक पहुँचाने, खातों को पुनः सक्रिय करने और सही दावेदारों को उनकी अनक्लेम्ड राशि लौटाने के लिए प्रेरित करती है।

Ques: What type of deposit insurance premium model has been proposed by the Reserve Bank of India (RBI)?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने किस प्रकार का डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम मॉडल प्रस्तावित किया है?

- A. Flat-rate premium model / समान दर प्रीमियम मॉडल
- B. Interest-linked premium model / ब्याजआधारित प्रीमियम मॉडल-
- C. Risk-based premium model / जोखिमआधारित प्रीमियम मॉडल-
- D. Credit growth-based model / ऋणवृद्धि आधारित मॉडल-
- E. Market-linked model / बाजारलगा मॉडलसं-

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has proposed a risk-based deposit insurance premium model, replacing the earlier flat-rate system where all banks paid a uniform premium of 12 paise per ₹100 of deposits to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC).
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पुराने फ्लैटरेट सिस्टम को बदलते हुए- जोखिमआधारित - डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम मॉडल प्रस्तावित किया है, जिसमें सभी बैंक समान प्रीमियम नहीं देंगे।
- Under this model, financially stronger and well-managed banks will pay lower premiums, while weaker banks will pay higher premiums.
- इस मॉडल के तहत वित्तीय रूप से मजबूत और सुव्यवस्थित बैंक कम प्रीमियम, और कमजोर बैंक अधिक प्रीमियम देंगे।
- Importantly, the deposit insurance cover of ₹5 lakh per depositor per bank (including principal and interest) will remain unchanged.
- महत्वपूर्ण रूप से, प्रत्येक जमाकर्ता प्रति बैंक ₹5 लाख तक की डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर अपरिवर्तित रहेगी।

- Detailed guidelines for implementation will be issued soon, likely effective from FY 2026.
- इस मॉडल को लागू करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जल्द जारी किए जाएंगे और यह अगले वित्त वर्ष (FY 2026) से लागू होने की संभावना है।

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) :

- Established: 1961
- Headquarters: Mumbai
- Parent Organisation: Reserve Bank of India (RBI)
- Current Deposit Insurance Cover: ₹5 lakh per depositor per bank
- Current Premium (before change): ₹0.12 per ₹100 of deposits (Flat Rate)

Ques: By how much has RBI recently raised the limits for IPO financing and loans against shares?

RBI ने हाल ही में IPO फाइनेंसिंग और शेयरों के खिलाफ लोन की सीमा कितनी बढ़ाई है?

- A. ₹10 Lakh to ₹20 Lakh
- B. ₹10 Lakh to ₹25 Lakh and ₹20 Lakh to ₹50 Lakh
- C. ₹10 Lakh to ₹25 Lakh and ₹20 लाख to ₹1 Crore
- D. ₹5 Lakh to ₹15 Lakh
- E. ₹5 Lakh to ₹35 Lakh

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has proposed raising the IPO financing limit from ₹10 lakh to ₹25 lakh per individual.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने IPO फाइनेंसिंग सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख प्रति व्यक्ति करने का प्रस्ताव रखा है।
- The limit for Loans Against Shares (LAS) will increase sharply from ₹20 lakh to ₹1 crore.
- Loans Against Shares (LAS) की सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ की जाएगी।
- These higher limits also apply to REITs and InvITs, aiming to encourage High-Net-Worth Individuals (HNIs) and deepen engagement in the primary market.

- ये बढ़ी हुई सीमाएं REITs और InvITs पर भी लागू होंगी, जिसका उद्देश्य उच्च निवल मूल्य वाले निवेशकों (HNIs) की भागीदारी बढ़ाना और प्राथमिक बाजार में गहराई लाना है।
- RBI noted that these limits were unchanged for many years despite improvements in banking capacity, necessitating the update.
- RBI ने कहा कि बैंकिंग क्षमता में सुधार के बावजूद ये सीमाएं कई वर्षों से अपरिवर्तित थीं, इसलिए अब उन्हें अपडेट किया जा रहा है।

Ques: The newly formed Payments Regulatory Board (PRB) by RBI replaces which of the following?

RBI द्वारा गठित नया भुगतान विनियामक बोर्ड (PRB) निम्नलिखित में से किसकी जगह बना है?

- A. Board for Financial Supervision (BFS) / वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड
- B. Monetary Policy Committee (MPC) / मौद्रिक नीति समिति
- C. Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems (BPSS) / भुगतान एवं निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड
- D. Financial Stability Board (FSB) / वित्तीय स्थिरता बोर्ड
- E. Digital Payment Council (DPC) / डिजिटल भुगतान परिषद

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has constituted a six-member Payments Regulatory Board (PRB) under the Payment and Settlement Systems Act, 2007, replacing the earlier Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems (BPSS), which was a committee of the RBI Central Board.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने छहसदस्यीय भुगतान विनियामक बोर्ड (PRB) को भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत गठित किया है, और इसने पहले के भुगतान एवं निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS) की जगह ली, जो RBI के केंद्रीय बोर्ड की एक समिति थी।
- Unlike the earlier five-member BPSS, the new PRB includes government nominees, giving the government a role in payment system oversight.
- पहले के पांच सदस्यीय-BPSS के विपरीत, नए PRB में सरकारी नामांकित सदस्य शामिल हैं, जिससे सरकार को भुगतान प्रणाली की निगरानी में भूमिका मिली है।

Ques: Which major reforms did the RBI recently announce for the cooperative banking sector?

आरबीआई ने हाल ही में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए कौन से प्रमुख सुधारों की घोषणा की है?

- A. Introduction of new digital banking platforms / नए डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत
- B. Reexamination of licensing framework for UCBs and expansion of grievance redressal system / UCBs के लिए लाइसेंसिंग ढांचे की पुनः समीक्षा और शिकायत निवारण प्रणाली का विस्तार
- C. Merger of all cooperative banks with commercial banks / सभी सहकारी बैंकों का वाणिज्यिक बैंकों के साथ विलय
- D. Reduction in repo rate for cooperative banks / सहकारी बैंकों के लिए रेपो दर में कमी
- E. Introduction of private equity participation in cooperative banks / सहकारी बैंकों में निजी इक्विटी भागीदारी की शुरुआत

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) announced two landmark proposals with significant implications for the cooperative banking sector.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों की घोषणा की, जिनका व्यापक प्रभाव होगा।
- RBI Governor Sanjay Malhotra stated that the central bank will reexamine the licensing framework for Urban Co-operative Banks (UCBs) after more than two decades, as licensing for new UCBs has been paused since 2004 due to supervisory and governance concerns.
- आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि केंद्रीय बैंक शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए लाइसेंसिंग ढांचे की दो दशकों से अधिक समय बाद पुनः समीक्षा करेगा, क्योंकि 2004 से नई UCBs के लिए लाइसेंसिंग रुक गई थी, निगरानी और शासन संबंधी चिंताओं के कारण।
- Additionally, the RBI announced a major consumer-centric reform by revamping its grievance redressal system.
- इसके साथ ही, आरबीआई ने अपने शिकायत निवारण प्रणाली को पुनर्गठित कर एक महत्वपूर्ण उपभोक्ताकेंद्रित सुधार की घोषणा की।

- The Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS), which currently covers commercial banks, NBFCs, and select financial entities, will now be extended to include rural cooperative banks for the first time.
- एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (RB-IOS), जो वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों, NBFCs और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं को कवर करती है, अब ग्रामीण सहकारी बैंकों को भी पहली बार इसमें शामिल किया जाएगा।
- This means District Central Cooperative Banks (DCCBs) and State Cooperative Banks (StCBs) will come under the direct ambit of RBI's ombudsman mechanism.
- इसका मतलब है कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंक (StCBs) अब सीधे आरबीआई के ओम्बड्समैन तंत्र के अंतर्गत आएंगे।

Ques: Which major step has been taken by RBI in its final guidelines on "Forms of Business and Prudential Regulation for Investments"?

RBI ने "Forms of Business and Prudential Regulation for Investments" की अंतिम गाइडलाइन्स में कौन सा प्रमुख कदम उठाया है?

- A. Increased capital requirement for NBFCs / NBFCs के लिए पूंजी आवश्यकता बढ़ाई
- B. Removed proposed restriction on overlap between banks and group entities / बैंकों और समूह संस्थाओं के बीच ओवरलैप पर प्रस्तावित प्रतिबंध हटाया
- C. Imposed limits on banks' lending to NBFCs / NBFCs को बैंक से उधार लेने पर सीमा लगाई
- D. Restricted IPO participation of bank subsidiaries / बैंक सहायक कंपनियों की IPO भागीदारी प्रतिबंधित की
- E. Introduced new investment ceiling for mutual funds / म्यूचुअल फंड्स के लिए नई निवेश सीमा लागू की

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The RBI has withdrawn the earlier proposed restrictions on overlapping business activities between banks and their group entities, including NBFCs and investment arms.
- आरबीआई ने बैंकों और उनकी समूह इकाइयों (जैसे) NBFCs और निवेश शाखाओं के बीच (

समान व्यवसाय करने पर प्रस्तावित प्रतिबंध हटा दिया है।

- This decision allows large private banks like HDFC, ICICI, Axis, and Kotak to maintain operational flexibility and pursue strategic business plans for their subsidiaries.
- इस निर्णय से HDFC, ICICI, Axis और Kotak जैसे बड़े निजी बैंक अपनी संचालनात्मक लचीलापन बनाए रख सकेंगे और अपनी सहायक कंपनियों के लिए रणनीतिक योजनाओं को आगे बढ़ा सकेंगे।
- The move also eases IPO and investment plans for group NBFCs, which were earlier impacted by the overlap rule.
- इस कदम से समूह NBFCs के IPO और निवेश योजनाओं में पहले लगे ओवरलैप नियम का प्रभाव कम होगा।

Ques: In October 2025, the RBI's Monetary Policy Committee decided to keep the repo rate unchanged at –

अक्टूबर 2025 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर यथावत रखा?

- A. 5.25%
- B. 5.5%
- C. 5.75%
- D. 6%
- E. 6.25%

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Monetary Policy Committee (MPC) of the Reserve Bank of India (RBI) decided to keep the benchmark repo rate unchanged at 5.5% in its October 2025 meeting — the second consecutive time.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अक्टूबर 2025 की बैठक में बेंचमार्क रेपो रेट को 5.5% पर यथावत रखा, जो लगातार दूसरी बार है।
- The policy stance was also maintained as 'Neutral'.
- नीति का रुख भी 'न्यूट्रल' (तटस्थ) रखा गया।
- Accordingly, Standing Deposit Facility (SDF) Rate is 5.25%, Marginal Standing Facility (MSF) Rate & Bank Rate is 5.75%.

- इसके अनुसार, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) दर 5.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) दर तथा बैंक रेट 5.75% है।
- RBI noted that the overall inflation outlook has turned more benign due to a sharp fall in food prices. The average headline inflation for FY25 has been revised down to 2.6% from the earlier 3.1%.
- आरबीआई ने कहा कि कुल मिलाकर मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण अब अधिक स्थिर हो गया है, मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में तेज गिरावट के कारण। FY25 के लिए औसत मुद्रास्फीति दर को 3.1% से घटाकर 2.6% कर दिया गया है।
- The FY26 GDP growth projection has been revised upward to 6.8% from the earlier estimate of 6.5%.
- FY26 की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया गया है।
- RBI also announced a Risk-Based Premium Framework for Deposit Insurance, allowing financially sound banks to pay lower premiums, effective from the next financial year.
- RBI ने डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए जोखिमआधारित प्रीमियम ढांचा- लागू करने की घोषणा की, जिससे वित्तीय रूप से सशक्त बैंक कम प्रीमियम देंगे। यह अगले वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगा।

Ques: Which institution recently unveiled its most comprehensive reforms in over a decade to expand corporate credit and deepen capital market activity?

किस संस्था ने हाल ही में एक दशक से अधिक समय में अपने सबसे व्यापक सुधारों का अनावरण किया है ताकि कॉर्पोरेट ऋण का विस्तार हो और पूंजी बाजार की गतिविधि गहराई जाए?

- A. Securities and Exchange Board of India (SEBI) / भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
- B. Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक
- C. Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- D. NITI Aayog / नीति आयोग
- E. Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) / भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Reserve Bank of India unveiled its most comprehensive reforms in over a decade, aimed at countering US-driven headwinds and expanding credit to companies while deepening capital market activity.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक दशक से अधिक समय में अपने सबसे व्यापक सुधारों का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य अमेरिकी प्रभाव से उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करना और कॉर्पोरेट ऋण के विस्तार के साथ पूंजी बाजार की गतिविधियों को गहराई देना है।
- Banks can now finance mergers, acquisitions, and IPOs more freely, while limits on loans against shares and listed debt securities have been raised.
- बैंक अब विलय, अधिग्रहण और आईपीओ को अधिक स्वतंत्र रूप से वित्तपोषित कर सकेंगे, साथ ही शेयरों और सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के विरुद्ध ऋण सीमा भी बढ़ा दी गई है।
- Borrowing rules for companies with loans above Rs 10,000 crore have been eased by removing earlier caps and extra capital requirements.
- 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण वाली कंपनियों के लिए उधार नियमों को आसान बनाया गया है, पहले की सीमा और अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताओं को हटाकर।
- Loans against shares have been increased from Rs 20 lakh to Rs 1 crore per individual, and IPO financing limits from Rs 10 lakh to Rs 25 lakh per person.
- शेयरों के विरुद्ध ऋण की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई है, और आईपीओ वित्तपोषण सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई है।
- These reforms, effective from October 2025, aim to expand credit access, improve liquidity, and encourage broader participation in equity markets.
- ये सुधार, जो अक्टूबर 2025 से प्रभावी होंगे, का उद्देश्य ऋण पहुंच का विस्तार करना, तरलता में सुधार करना और इक्विटी बाजारों में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

Ques: What is the main objective of RBI's proposal to reduce risk weights for NBFCs' infrastructure loans?

RBI के प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसमें NBFCs के इंफ्रास्ट्रक्चर लोन पर जोखिम भार घटाने की बात कही गई है?

- A. To increase tax benefits for NBFCs / NBFCs के लिए कर लाभ बढ़ाना
- B. To reduce cost of infrastructure financing and promote long-term lending / इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की लागत कम करना और दीर्घकालिक ऋण प्रवाह को बढ़ावा देना
- C. To stop NBFCs from giving infra loans / NBFCs को इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देने से रोकना
- D. To merge NBFCs with banks / NBFCs को बैंकों में विलय करना

E. To raise deposit insurance limit / जमा बीमा सीमा बढ़ाना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The RBI has proposed reducing risk weights for NBFCs' loans to operational and high-quality infrastructure projects.
 - आरबीआई ने NBFCs द्वारा संचालित और उच्च गुणवत्ता वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जोखिम भार घटाने का प्रस्ताव रखा है।
 - This move will lower financing costs for NBFCs and encourage more long-term, sound lending in the infrastructure sector.
 - इस कदम से NBFCs की फाइनेंसिंग लागत कम होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में दीर्घकालिक और सुरक्षित ऋण प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा।
 - The framework also ensures better risk assessment and capital optimization, while promoting competitiveness among NBFCs.
 - यह ढांचा बेहतर जोखिम मूल्यांकन और पूंजी अनुकूलन सुनिश्चित करेगा, साथ ही NBFCs के बीच प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देगा।
-

Ques: Which ministry is coordinating the nationwide campaign “आपकी पूंजी, आपका अधिकार” — Your Money, Your Right?

“आपकी पूंजी, आपका अधिकार” — Your Money, Your Right नामक राष्ट्रीय अभियान का समन्वय कौन सा मंत्रालय कर रहा है?

- A. Ministry of Corporate Affairs / कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
- B. Ministry of Consumer Affairs / उपभोक्ता मामले मंत्रालय
- C. Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- D. Ministry of Home Affairs / गृह मंत्रालय
- E. Ministry of Labour / श्रम मंत्रालय

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Department of Financial Services (DFS) under the Ministry of Finance is

coordinating the nationwide awareness campaign on unclaimed financial assets in collaboration with RBI, IRDAI, SEBI, and IEPFA.

- वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग (DFS) इस अभियान का समन्वय RBI, IRDAI, SEBI, और IEPFA के सहयोग से कर रहा है।
- The campaign, titled “आपकी पूंजी, आपका अधिकार” (Your Money, Your Right), will run from October to December 2025 and aims to guide citizens on claiming their unclaimed financial assets.
- यह अभियान “आपकी पूंजी, आपका अधिकार” शीर्षक से अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक चलेगा और इसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी अप्राप्त वित्तीय संपत्तियों का दावा करने में मार्गदर्शन देना है।

Ques: What new facility has the RBI allowed for NRIs regarding investment in India?

भारत में निवेश के संबंध में RBI ने NRI को कौन सी नई सुविधा दी है?

- A. NRIs can invest in Indian mutual funds through rupee accounts. / NRI रुपये खातों से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं।
- B. NRIs can invest in Indian debt market through rupee accounts. / NRI रुपये खातों से भारतीय ऋण बाजार में निवेश कर सकते हैं।
- C. NRIs can invest in real estate using rupee accounts. / NRI रुपये खातों से रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं।
- D. NRIs can invest in gold bonds only. / NRI केवल गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं।
- E. NRIs can open rupee accounts for remittance only. / NRI रुपये खाते केवल प्रेषण के लिए खोल सकते हैं।

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has amended the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016, to allow NRIs to invest in non-convertible debentures (NCDs), bonds, and commercial papers through their rupee accounts.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम (जमा), 2016 में संशोधन किया है ताकि NRI रुपये खातों के माध्यम से गैरपरिवर्तनीय डिबेंचर-, बॉन्ड और वाणिज्यिक पत्रों में

निवेश कर सकें।

- This facility aims to facilitate debt investment, strengthen the internationalisation of the Indian rupee, boost India's debt market, reduce borrowing costs, and support GDP growth, especially in infrastructure and renewable energy sectors.
- इस सुविधा का उद्देश्य ऋण निवेश को सुगम बनाना, रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण को मजबूत करना, भारत के ऋण बाजार को बढ़ावा देना, उधारी की लागत को कम करना और विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर व नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में GDP वृद्धि को बढ़ावा देना है।

Ques: What is the purpose of the Mutual Fund Investment Tracing and Retrieval Assistant (MITRA) platform launched by SEBI?

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा लॉन्च किए गए म्यूचुअल फंड निवेश ट्रेसिंग और रिट्रीवल असिस्टेंट (MITRA) प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है?

- A. To provide tax benefits on mutual fund investments / म्यूचुअल फंड निवेश पर कर लाभ प्रदान करना
- B. To help investors track and reclaim inactive or unclaimed mutual fund folios / निवेशकों को निष्क्रिय या अप्राप्त म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक और पुनः प्राप्त करने में मदद करना
- C. To offer high-risk mutual fund schemes / उच्च जोखिम वाले म्यूचुअल फंड योजनाएं पेश करना
- D. To facilitate direct mutual fund purchases without brokers / ब्रोकर के बिना सीधे म्यूचुअल फंड खरीदने की सुविधा प्रदान करना
- E. To provide educational courses on mutual fund investing / म्यूचुअल फंड निवेश पर शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रदान करना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- SEBI launched the Mutual Fund Investment Tracing and Retrieval Assistant (MITRA) to help investors track and reclaim inactive or unclaimed Mutual Fund folios.
- SEBI ने निवेशकों को निष्क्रिय या अप्राप्त म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक और पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए म्यूचुअल फंड निवेश ट्रेसिंग और रिट्रीवल असिस्टेंट (MITRA)

लॉन्च किया।

- The platform was introduced under SEBI's regulatory powers to protect investor interests and promote orderly development of the securities market.
- यह प्लेटफॉर्म निवेशक हितों की सुरक्षा और प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए SEBI के नियामक शक्तियों के तहत पेश किया गया।
- MITRA is jointly managed by two Qualified Registrar and Transfer Agents: CAMS and KFin Technologies Limited.
- MITRA का प्रबंधन दो योग्य रजिस्टार और ट्रांसफर एजेंट्स, CAMS और KFin Technologies Limited, द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

Ques: Who has joined the board of the Fintech Association for Consumer Empowerment (FACE) as an Independent Director?

फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट (FACE) के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसने बोर्ड जॉइन किया है?

- A. M. Rajeshwar Rao / एमराजेश्वर राव .
- B. T. Rabi Sankar / टीरबी शंकर .
- C. Manoranjan Mishra / मनोरंजन मिश्रा
- D. Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास
- E. Sugandh Saxena / सुगंध सक्सेना

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Former RBI Executive Director Manoranjan Mishra has been appointed as an Independent Director on the board of the Fintech Association for Consumer Empowerment (FACE).
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा को फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट (FACE) के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- FACE, recognized by RBI as an SRO-FT, is a self-regulatory body for fintech companies in India.
- FACE, जिसे RBI द्वारा SRO-FT के रूप में मान्यता प्राप्त है, भारत में फिनटेक कंपनियों के लिए एक स्वनियामक संस्था है।-

- Mishra's experience is expected to guide FACE in promoting innovation, growth, development, and consumer protection in the fintech sector.
- मिश्रा का अनुभव FACE को फिनटेक क्षेत्र में नवाचार, विकास और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने में मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

Ques: What is the new deadline set by SEBI for the complete rollout of algorithm trading rules for retail investors?

SEBI ने खुदरा निवेशकों के लिए एल्गोरिथम ट्रेडिंग नियमों के पूर्ण कार्यान्वयन की नई समय सीमा क्या तय की है?

- A. October 01, 2025
- B. January 03, 2026
- C. August 01, 2025
- D. November 30, 2025
- E. April 01, 2026

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has extended the deadline for the complete rollout of algorithm trading rules for retail investors to April 01, 2026.
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने खुदरा निवेशकों के लिए एल्गोरिथम ट्रेडिंग नियमों के पूर्ण कार्यान्वयन की समय सीमा 1 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी है।
- Retail Algo Trading allows investors to use automated trading strategies through computer programs.
- रिटेल एल्गो ट्रेडिंग निवेशकों को कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से स्वचालित ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग करने की अनुमति देती है।
- The framework, initially set for August 01, 2025, was first deferred to October 01, 2025, and now extended further.
- यह ढांचा पहले 1 अगस्त 2025 से लागू होना था, फिर इसे 1 अक्टूबर 2025 तक स्थगित किया गया और अब आगे बढ़ाया गया है।
- Brokers failing to meet these milestones will be barred from onboarding new retail clients after January 05, 2026.
- जो ब्रोकर्स इन माइलस्टोन का पालन नहीं करेंगे, उन्हें 5 जनवरी 2026 से नए रिटेल

क्लाइंट जोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

- The complete algo framework will become mandatory for all brokers from April 01, 2026.
- पूरा एल्गो फ्रेमवर्क 1 अप्रैल 2026 से सभी ब्रोकर्स के लिए अनिवार्य होगा।

SEBI has introduced a glide path with 3 key milestones for phased implementation:

SEBI ने चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए 3 प्रमुख माइलस्टोन तय किए हैं:

- Milestone 1: Brokers must apply for registration of at least one retail algo strategy by October 31, 2025.
- माइलस्टोन 1: 31 अक्टूबर 2025 तक कम से कम एक रिटेल एल्गो रणनीति के पंजीकरण के लिए आवेदन।
- Milestone 2: Full registration of retail algo products by November 30, 2025.
- माइलस्टोन 2: 30 नवंबर 2025 तक एल्गो उत्पादों का पूरा पंजीकरण।
- Milestone 3: Brokers must participate in a mock trading session by January 03, 2026.
- माइलस्टोन 3: 3 जनवरी 2026 तक मॉक ट्रेडिंग सत्र में भाग लेना।

Ques: Which organisation has been granted SRO status by the RBI for the non-bank lending sector?

गैरबैंकिंग ऋण क्षेत्र के लिए RBI ने किस संगठन को SRO का दर्जा दिया है?

- A. NAFR / NAFR
- B. FINO Council / FINO काउंसिल
- C. FIDC / FIDC
- D. MFIN / MFIN
- E. IBA / IBA

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) granted Self-Regulatory Organisation (SRO) status to the Finance Industry Development Council (FIDC) to promote self-

regulation and ensure compliance in the non-bank lending sector.

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल (FIDC) को गैरबैंकिंग - ऋण क्षेत्र में आत्म नियमन और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए-SRO का दर्जा दिया है।
- FIDC is a representative body of NBFCs registered with the RBI and will help improve governance, transparency, and fair representation for smaller NBFCs.
- FIDC, RBI के साथ पंजीकृत NBFCs का एक प्रतिनिधि संगठन है और यह प्रशासन, पारदर्शिता और छोटे NBFCs के लिए उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
- To be recognised as an SRO, FIDC meets conditions like being a non-profit under Section 8 of the Companies Act, having minimum net worth of ₹2 crore, and including at least 10% of Base Layer NBFCs as members.
- SRO के रूप में मान्यता पाने के लिए FIDC गैरलाभकारी संस्था होना चाहिए-, न्यूनतम ₹2 करोड़ की निवल संपत्ति हो और बेस लेयर के कम से कम 10% NBFCs को सदस्य के रूप में शामिल करना होगा।

Ques: From which date will UIDAI's revised Aadhaar service charges become effective?

UIDAI की संशोधित आधार सेवा शुल्क दरें किस तारीख से प्रभावी होंगी?

- A. July 1, 2025 / 1 जुलाई 2025
- B. October 1, 2025 / 1 अक्टूबर 2025
- C. January 1, 2026 / 1 जनवरी 2026
- D. September 30, 2025 / 30 सितंबर 2025
- E. April 1, 2026 / 1 अप्रैल 2026

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- UIDAI announced a revision in Aadhaar-related service charges, effective from October 1, 2025, to September 30, 2028.
- UIDAI ने आधार सेवाओं के शुल्कों में संशोधन किया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2028 तक प्रभावी रहेगा।
- Under the new rates, ₹50 services will increase to ₹75, and ₹100 services will

increase to ₹125. From October 2028, these will further rise to ₹90 and ₹150 respectively.

- नई दरों के अनुसार, ₹50 की सेवाओं की फीस ₹75 और ₹100 की सेवाओं की फीस ₹125 होगी। अक्टूबर 2028 से यह क्रमशः ₹90 और ₹150 हो जाएगी।
- Biometric updates for children aged 5–7 and 15–17 years will remain free, while updates for 7–15-year-olds will be free until September 30, 2026, to reduce Mandatory Biometric Update (MBU) pendency.
- 5–7 और 15–17 वर्ष के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट निशुल्क रहेंगे; जबकि 7–15 वर्ष के बच्चों के लिए यह 30 सितंबर 2026 तक निशुल्क रहेगा ताकि MBU लंबित मामलों को कम किया जा सके।

Ques: As per the draft Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA) Directions, 2025 issued by the Reserve Bank of India (RBI), by when will the new framework be implemented?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉज़िट अकाउंट (BSBDA) दिशानिर्देश, 2025 के अनुसार नया ढांचा कब तक लागू किया जाएगा?

- A. December 31, 2025
- B. January 31, 2026
- C. April 30, 2026
- D. March 31, 2026
- E. June 30, 2026

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) issued the draft of the Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA) Directions, 2025, applicable to all banks.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों पर लागू होने वाले बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉज़िट अकाउंट (BSBDA) दिशानिर्देश, 2025 का मसौदा जारी किया।
- The framework is set to be implemented by March 31, 2026.
- यह ढांचा 31 मार्च 2026 तक लागू किया जाएगा।
- Every bank must offer BSBD accounts with certain minimum facilities free of charge, regardless of a minimum balance.
- प्रत्येक बैंक को न्यूनतम बैलेंस की परवाह किए बिना कुछ न्यूनतम सुविधाओं के साथ मुफ्त

BSBD खाता प्रदान करना अनिवार्य होगा।

- These free facilities include an ATM/Debit Card (with no annual fee), a cheque book with at least 25 leaves per year, and internet/mobile banking.
- इन मुफ्त सेवाओं में एटीएम(बिना वार्षिक शुल्क) डेबिट कार्ड/, प्रति वर्ष कम से कम 25 पन्नों वाली चेक बुक, और इंटरनेटमोबाइल बैंकिंग शामिल हैं।/
- A minimum of four free withdrawals per month is allowed, excluding digital payments like UPI, NEFT, RTGS, IMPS, etc.
- प्रति माह न्यूनतम चार मुफ्त निकासी की अनुमति दी जाएगी, जिसमें UPI, NEFT, RTGS, IMPS आदि जैसे डिजिटल भुगतान शामिल नहीं होंगे।
- Account holders cannot maintain another savings account in the same or any other bank simultaneously.
- खाता धारक एक ही समय में उसी या किसी अन्य बैंक में कोई अन्य बचत खाता नहीं रख सकते।

Ques: Which two initiatives has SEBI launched to enhance payment security and curb fraudulent fund collections?

भुगतान सुरक्षा बढ़ाने और धोखाधड़ी वाले फंड संग्रह को रोकने के लिए सेबी ने कौन सी दो पहलें शुरू की हैं?

- A. UPI Safe & SEBI Verify / यूपीआई सेफ और सेबी वेरीफाई
- B. Validated UPI Handles & SEBI Check / वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल और सेबी चेक
- C. Investor Shield & UPI Trust / इन्वेस्टर शील्ड और यूपीआई ट्रस्ट
- D. Saarthi Pay & SafeHandle / सार्थी पे और सेफ हैंडल
- E. SEBI SecurePay & UPI Trust / सेबी सिक्योरपे और यूपीआई ट्रस्ट

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- SEBI launched Validated UPI Handles and SEBI Check to ensure secure payments and reduce fraud in fund transactions.
- सेबी ने Validated UPI Handles और SEBI Check की शुरुआत की ताकि भुगतान सुरक्षित रहें और फंड ट्रांजेक्शन में धोखाधड़ी को कम किया जा सके।
- A new exclusive “@valid” UPI handle will be used by SEBI-registered intermediaries, including brokers and mutual funds, with category-specific

suffixes like “.brk” for brokers and “.mf” for mutual funds.

- नया “@valid” यूपीआई हैंडल अब सेबीपंजीकृत बिचौलियों जैसे ब्रोकर और म्यूचुअल - फंड्स द्वारा उपयोग किया जाएगा, जिसमें “.brk” ब्रोकरों और “.mf” म्यूचुअल फंड्स के लिए श्रेणीविशिष्ट प्रत्यय होंगे।
- SEBI Check allows investors to independently verify bank account details and UPI IDs of intermediaries through the Saarthi app or SEBI’s platform.
- SEBI Check निवेशकों को सार्थी ऐप या सेबी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिचौलियों के बैंक खाता विवरण और यूपीआई ID की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने की सुविधा देता है।

Ques: Which organisation has provided a USD 190 million loan for the Indore Metro Rail Project?

किस संगठन ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है?

- A. World Bank / विश्व बैंक
- B. International Monetary Fund (IMF) / अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
- C. New Development Bank (NDB) / न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)
- D. Japan International Cooperation Agency (JICA) / जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA)
- E. Asian Development Bank (ADB) / एशियाई विकास बैंक (ADB)

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- The Asian Development Bank (ADB) has approved a USD 190 million loan for the Indore Metro Rail Project in Madhya Pradesh.
- एशियाई विकास बैंक (ADB) ने मध्य प्रदेश की इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है।
- The project is being implemented by the Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited (MPMRCL) and is expected to be operational by January 2030.
- इस परियोजना को मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MPMRCL) द्वारा लागू किया जा रहा है और इसे जनवरी 2030 तक चालू करने की योजना है।
- The loan will finance the construction of an 8.62 km-long underground metro

line with 7 stations to enhance urban mobility and reduce traffic congestion in Indore.

• यह ऋण 8.62 किलोमीटर लंबी भूमिगत मेट्रो लाइन के 7 स्टेशनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिससे इंदौर में शहरी परिवहन में सुधार और यातायात जाम में कमी आएगी।

Ques: As per RBI's draft proposal, what is the maximum materiality threshold for lending to related parties for large banks with asset size above ₹10 lakh crore?

आरबीआई के ड्राफ्ट प्रस्ताव के अनुसार, ₹10 लाख करोड़ से अधिक परिसंपत्ति वाले बड़े बैंकों के लिए संबंधित पक्षों को ऋण देने की अधिकतम सीमा क्या होगी?

- A. ₹5 crore
- B. ₹10 crore
- C. ₹25 crore
- D. ₹50 crore
- E. ₹1 crore

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- RBI's draft framework proposes scale-based materiality thresholds for banks and NBFCs for loans to related parties, including personal loans to directors.
- आरबीआई के ड्राफ्ट ढांचे के अनुसार, बैंकों और एनबीएफसी के लिए संबंधित पक्षों को दिए जाने वाले ऋणों पर स्केल-आधारित मटीरियलिटी सीमा प्रस्तावित की गई है, जिसमें निदेशकों को व्यक्तिगत ऋण भी शामिल हैं।
- For large banks with assets above ₹10 lakh crore, the maximum permissible lending limit to related parties is ₹50 crore. Smaller banks have proportionately lower thresholds (₹5 crore and ₹10 crore).
- ₹10 लाख करोड़ से अधिक परिसंपत्ति वाले बड़े बैंकों के लिए संबंधित पक्षों को ऋण देने की अधिकतम सीमा ₹50 करोड़ होगी। छोटे बैंकों के लिए यह क्रमशः ₹5 करोड़ और ₹10 करोड़ निर्धारित है।

Ques: The Reserve Bank of India (RBI) has granted an extension of tenure to Raghavendra Srinivas Bhat as MD & CEO of which bank?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने राघवेंद्र श्रीनिवास भट के कार्यकाल को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में बढ़ाया है?

- A. South Indian Bank / साउथ इंडियन बैंक
- B. Karnataka Bank / कर्नाटक बैंक
- C. Federal Bank / फेडरल बैंक
- D. Karur Vysya Bank / करूर वैश्य बैंक
- E. City Union Bank / सिटी यूनियन बैंक

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has approved a one-month extension in the tenure of Raghavendra Srinivas Bhat as the MD & CEO of Karnataka Bank.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने राघवेंद्र श्रीनिवास भट को कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में एक माह का कार्यकाल विस्तार प्रदान किया है।
- The extension will be effective from October 16, 2025, or until the appointment of a regular MD & CEO, whichever is earlier.
- यह विस्तार 16 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा या नियमित एमडी और सीईओ की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो।
- Karnataka Bank is a private sector bank headquartered in Mangaluru, Karnataka.
- कर्नाटक बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय मंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है।

Ques: Which reforms were announced by the Reserve Bank of India (RBI) alongside the Monetary Policy Committee (MPC) meeting to strengthen the banking sector?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के साथ कौन से सुधारों की घोषणा की?

- A. Risk Based Premium Framework, ECL Provisioning, Revised Basel III norms, Capital Market Lending Reforms / जोखिम आधारित प्रीमियम ढांचा, ECL प्रावधान,

संशोधित बेसल III मानदंड, पूंजी बाजार ऋण सुधार

B. Repo Rate Cut, CRR Hike, Forex Market Reforms, NBFC Liquidity Scheme / रेपो दर में कटौती, सीआरआर वृद्धि, विदेशी मुद्रा बाजार सुधार, एनबीएफसी तरलता योजना

C. Digital Rupee Expansion, Credit Card Framework, UPI Internationalisation, Bond Market Reform / डिजिटल रुपया विस्तार, क्रेडिट कार्ड ढांचा, यूपीआई अंतर्राष्ट्रीयकरण, बॉन्ड बाजार सुधार

D. Gold Monetisation Scheme, Banking Merger Policy, Priority Sector Lending Expansion / स्वर्ण मुद्राकरण योजना, बैंकिंग विलय नीति, प्राथमिक क्षेत्र ऋण विस्तार

E. Inflation Targeting Framework, FPI Investment Reform, Exchange Rate Stabilisation Measures / मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण ढांचा, एफपीआई निवेश सुधार, विनिमय दर स्थिरीकरण उपाय

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) announced four major reforms alongside the Monetary Policy Committee (MPC) meeting to enhance the resilience of the banking sector and streamline regulatory processes.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के साथ बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता और नियामक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए चार प्रमुख सुधारों की घोषणा की।

Risk Based Premium Framework for Deposit Insurance

- Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) will now charge banks based on their risk profile instead of a flat rate of 12 paise per ₹100 of deposits.
- डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) अब बैंकों से उनकी जोखिम प्रोफाइल के आधार पर प्रीमियम वसूलेगा, न कि ₹100 पर 12 पैसे की समान दर पर।

Expected Credit Loss (ECL) Provisioning Framework

- Replaces the "Incurred Loss Model" with a forward-looking system where banks estimate potential future losses based on borrower risk, repayment history, and economic conditions.
- यह "Incurred Loss Model" को बदलकर एक अग्रिम अनुमान मॉडल लाता है, जिसमें

बैंक उधारकर्ता की जोखिम प्रोफ़ाइल, पुनर्भुगतान इतिहास और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर भविष्य के संभावित नुकसान का अनुमान लगाते हैं।

Revised Basel III Capital Adequacy Norms

- To be effective from April 1, 2027, the updated framework lowers capital requirements for MSME and residential real estate loans, enhancing credit flow.
- 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होने वाले संशोधित ढांचे के तहत MSME और आवासीय रियल एस्टेट ऋणों के लिए पूंजी आवश्यकताओं को कम किया गया है, जिससे ऋण प्रवाह में सुधार होगा।

Broadening Capital Market Lending Scope

- Banks can now finance acquisitions by Indian corporations and have enhanced limits for lending against shares.
- बैंकों को अब भारतीय कंपनियों द्वारा अधिग्रहण के लिए वित्तपोषण करने और शेयरों के विरुद्ध ऋण देने की सीमा बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

About Expected Credit Loss (ECL) : Instead of waiting for a borrower to default, banks will now estimate how much loss they might face in the future — based on the borrower's risk profile, repayment history, economic conditions, etc

Ques: As per RBI's new draft ECB framework, what is the maximum amount firms can raise without prior approval?

आरबीआई के नए ईसीबी ड्राफ्ट के अनुसार, कंपनियां बिना पूर्व अनुमति के अधिकतम कितनी राशि तक उधार ले सकती हैं?

- A. \$500 million / \$500 मिलियन
- B. \$750 million / \$750 मिलियन
- C. \$1 billion or 300% of net worth (whichever is higher) / \$1 बिलियन या नेट वर्थ के 300% तक, जो भी अधिक हो
- D. \$2 billion / \$2 बिलियन
- E. \$50 million / \$50 मिलियन

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- RBI's draft External Commercial Borrowing (ECB) framework proposes to increase the borrowing limit for Indian firms from \$750 million to \$1 billion or 300% of net worth, whichever is higher, without needing prior approval.
- RBI के इस ड्राफ्ट के तहत कंपनियां \$750 मिलियन की जगह \$1 बिलियन या नेट वर्थ के 300% तक उधार ले सकती हैं, जो भी अधिक हो, और इसके लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- The framework also specifies a minimum 3-year maturity, with manufacturing firms allowed 1–3 years maturity if their total ECB does not exceed \$50 million.
- यह ढांचा न्यूनतम 3 वर्ष की परिपक्वता अवधि तय करता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियों को 1–3 वर्ष की अवधि की अनुमति दी गई है, यदि कुल ईसीबी \$50 मिलियन से अधिक नहीं है।

Ques: Which development bank reported a 19.5% growth in net profit for FY 2024–25, reaching ₹4,811 crore, with a focus on digital innovation, green finance, and financial inclusion?

किस विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024–25 में शुद्ध लाभ में 19.5% वृद्धि दर्ज की, ₹4,811 करोड़ तक पहुँचाया, और डिजिटल नवाचार, ग्रीन फाइनेंस और वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया?

- A. NABARD / नाबार्ड
- B. SIDBI / एसआईडीबीआई
- C. EXIM Bank / एक्सिम बैंक
- D. RBI / भारतीय रिज़र्व बैंक
- E. LIC / एलआईसी

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Small Industries Development Bank of India (SIDBI) reported a net profit

of ₹4,811 crore for FY 2024–25, registering a 19.5% growth over the previous year (FY24: ₹4,026 crore).

- लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) ने वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹4,811 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष (FY24: ₹4,026 करोड़) की तुलना में (19.5% की वृद्धि) है।
- SIDBI focuses on digital innovation, green finance, and financial inclusion, positioning itself as a key pillar of India's economic development.
- SIDBI डिजिटल नवाचार, ग्रीन फाइनेंस और वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करता है और भारत के आर्थिक विकास का एक प्रमुख स्तंभ बनता है।

Key Financial Metrics for FY25 / FY25 के प्रमुख वित्तीय संकेतक :

- Balance Sheet / Asset Base: ₹5,68,238 crore (↑ 8.7%)
 - बैलेंस शीट :संपत्ति आधार /₹5,68,238 करोड़)↑ 8.7%)
 - Loans & Advances Portfolio: ₹4,96,282 crore (↑ 8.8%)
 - ऋण और अग्रिम पोर्टफोलियो :₹4,96,282 करोड़)↑ 8.8%)
 - Total Income: ₹38,511 crore (↑ ~20.6% YoY)
 - कुल आय :₹38,511 करोड़)↑ ~20.6% वार्षिक(
- Asset Quality: Gross NPA at 0.04% and Net NPA at nil as of March 31, 2025.
 - संपत्ति गुणवत्ता :31 मार्च 2025 तक सकल NPA 0.04% और शुद्ध NPA शून्य रहा।

Ques: What is SBI's target for its asset size as a percentage of India's GDP by 2047?

2047 तक भारत की GDP के प्रतिशत के रूप में SBI का संपत्ति आकार लक्ष्य क्या है?

- A. 20%
- B. 22%
- C. 25%
- D. 30%
- E. 28%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- SBI Chairman C.S. Setty stated that the bank aims to expand its asset size from 20% to 25% of India's GDP by 2047.
- SBI के चेयरमैन सीसेठी ने कहा कि बैंक का लक्ष्य अपनी संपत्ति का आकार वर्तमान .एस. में भारत की GDP के 20% से बढ़ाकर 2047 तक 25% तक करना है।
- The bank plans to support emerging sectors like semiconductors, green hydrogen, and battery storage, aligning with India's "Viksit Bharat" vision.
- बैंक सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज जैसे उभरते क्षेत्रों में वित्तीय सहयोग देगा, जो भारत के "विकसित भारत" दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- SBI's global presence and overseas operations are also planned to grow, strengthening its position among the top 10–20 banks worldwide.
- SBI की वैश्विक उपस्थिति और विदेशी संचालन भी बढ़ाने की योजना है, जिससे यह विश्व के शीर्ष 10–20 बैंकों में शामिल होने की स्थिति मजबूत करेगा।

Ques: Which organization has introduced new guidelines to provide relief to financially stressed borrowers by easing loan repayment rules?

किस संगठन ने आर्थिक रूप से तनावग्रस्त उधारकर्ताओं को ऋण पुनर्भुगतान नियमों में राहत देने के लिए नई दिशानिर्देश जारी किए हैं?

- A. SEBI / सेबी
- B. Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- C. NABARD / नाबार्ड
- D. Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
- E. NITI Aayog / नीति आयोग

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has introduced new guidelines to provide relief to financially stressed borrowers by making loan terms more flexible and borrower-friendly.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आर्थिक रूप से तनावग्रस्त उधारकर्ताओं को राहत देने और ऋण शर्तों को अधिक लचीला व उधारकर्ता अनुकूल बनाने के लिए नई दिशानिर्देश जारी

किए हैं।

Key benefits / मुख्य लाभ:

- **Faster EMI relief:** Earlier, banks could not change the “spread” (extra margin) for 3 years even if RBI reduced benchmark rates. Now, RBI has removed this restriction, allowing banks to reduce interest rates faster when RBI cuts rates.
- **तेजी से EMI राहत:** पहले बैंक 3 साल तक “स्प्रेड” (अतिरिक्त मार्जिन) नहीं बदल सकते थे, भले ही RBI ब्याज दरें घटा दे। अब RBI ने यह प्रतिबंध हटा दिया है, जिससे बैंकों को ब्याज दर घटाने में आसानी होगी।
- **More choice at reset:** Borrowers with floating-rate loans can now choose to either continue with a floating rate or switch to a fixed rate at every interest rate reset (usually every 6 months).
- **रीसेट पर अधिक विकल्प:** फ्लोटिंग रेट लोन वाले उधारकर्ता अब हर ब्याज दर रीसेट-आमतौर पर हर)6 महीने पर यह चुन सकते हैं कि वे फ्लोटिंग रेट जारी रखें या फिक्स्ड (रेट पर स्विच करें)।
- **No penal interest:** Banks can no longer charge penalty interest for missed EMIs. Only a fixed late payment fee (e.g., ₹500 or ₹1000) can be applied.
- **कोई दंडात्मक ब्याज नहीं:** अब बैंक विलंबित EMI भुगतान पर दंडात्मक ब्याज नहीं लगा सकते। केवल एक निश्चित लेट फीस (जैसे) ₹500 या ₹1000) ही ली जा सकती है।
- **Restructuring or moratorium options:** Banks are required to support borrowers facing financial hardships (like job loss, business failure, or medical emergencies) through restructuring or temporary payment relief.
- **पुनर्गठन या मोरेटोरियम विकल्प:** यदि उधारकर्ता को नौकरी छूटने, व्यापार हानि या चिकित्सा आपात स्थिति जैसी समस्या हो, तो बैंक को दंडित करने के बजाय पुनर्गठन या अस्थायी राहत प्रदान करनी होगी।
- RBI says lenders should provide relief options such as : 1. Restructuring of Loan Tenure 2. EMI Moratorium 3. One-Time Settlement (OTS)
- RBI का कहना है कि ऋणदाताओं को निम्नलिखित राहत विकल्प प्रदान करने चाहिए: 1. ऋण अवधि का पुनर्गठन 2. EMI स्थगन 3. एकमुश्त निपटान (OTS)

Ques: Which bank, in collaboration with PhonePe, launched the Wish Credit Card powered by RuPay?

किस बैंक ने PhonePe के सहयोग से RuPay द्वारा संचालित Wish क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया?

- A. Utkarsh Small Finance Bank / उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक
- B. HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- C. ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- D. Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E. SBI Card / एसबीआई कार्ड

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- The Wish Credit Card was launched by PhonePe in collaboration with Utkarsh Small Finance Bank and is powered by RuPay.
- Wish क्रेडिट कार्ड को PhonePe ने Utkarsh Small Finance Bank के सहयोग से लॉन्च किया है और यह RuPay द्वारा संचालित है।
- The card is backed by a fixed deposit with a minimum deposit of Rs. 2,000.
- इस कार्ड को फिक्स्ड डिपॉजिट द्वारा समर्थित किया गया है, जिसमें न्यूनतम जमा राशि ₹2,000 है।

About Utkarsh Small Finance Bank:

- Headquarters: Varanasi, Uttar Pradesh
- CEO: Govind Singh
- Tagline: Aapki Umeed Ka Khata

Ques: Which company, in collaboration with HDFC Pension Management Company Limited, launched the National Pension System (NPS) Platform Workers Model under the supervision of PFRDA?

किस कंपनी ने एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के सहयोग से, पीएफआरडीए के पर्यवेक्षण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली र्स मॉडल लॉन्च कियाप्लेटफॉर्म वर्क (एनपीएस)?

- A. Swiggy / स्विगी
- B. Blinkit / ब्लिंकिट
- C. Ola / ओला
- D. Urban Company / अर्बन कंपनी
- E. Zomato / जोमैटो

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- Zomato, in collaboration with HDFC Pension Management Company Limited, launched the National Pension System (NPS) Platform Workers Model under the supervision of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).
- जोमैटो ने एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के सहयोग से, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के पर्यवेक्षण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल लॉन्च किया।
- The initiative aims to provide structured retirement planning for gig-based delivery partners and integrate them into the formal financial system.
- इस पहल का उद्देश्य गिगत डिलीवरी पार्टनर्स को सआधारि-रचित सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करना और उन्हें औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल करना है।
- Within the first 72 hours, over 30,000 delivery partners generated their Permanent Retirement Account Numbers (PRANs).
- पहले 72 घंटों के भीतर, 30,000 से अधिक डिलीवरी पार्टनर्स ने अपने स्थायी सेवानिवृत्ति खाता नंबर (PRAN) प्राप्त किए।
- Zomato aims to onboard more than 1,00,000 partners by December 2025.
- जोमैटो का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक 1,00,000 से अधिक पार्टनर्स को जोड़ने का है।
- The NPS Platform Workers Model is a special version of the National Pension System (NPS) designed specifically for gig and platform workers such as those working with Zomato, Swiggy, Ola, Uber, Blinkit, and Urban Company.
- एनपीएस प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का एक विशेष संस्करण है, जिसे जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर, ब्लिंकिट और अर्बन कंपनी जैसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए तैयार किया गया है।
- The model was formally launched by Finance Minister Nirmala Sitharaman on October 1 at an event organised by PFRDA.
- इस मॉडल को 1 अक्टूबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा PFRDA द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया।

Ques: In which country did Union Minister Piyush Goyal launch India's Unified Payments Interface (UPI) to enhance digital and financial cooperation?

किस देश में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने डिजिटल और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लॉन्च किया?

- A. Qatar / क़तर
- B. UAE / संयुक्त अरब अमीरात
- C. Saudi Arabia / सऊदी अरब
- D. Oman / ओमान
- E. Bahrain / बहरीन

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal launched India's Unified Payments Interface (UPI) at the Lulu Mall in Doha, Qatar, marking a new milestone in digital and financial cooperation between India and Qatar.
- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने क़तर के दोहा स्थित लुलु मॉल में भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लॉन्च किया, जो भारत और क़तर के बीच डिजिटल और वित्तीय सहयोग में एक नया मील का पत्थर है।
- UPI, launched nine years ago, now accounts for 85% of India's digital payments and nearly half of global digital transactions.
- UPI, जिसे नौ वर्ष पहले लॉन्च किया गया था, अब भारत के कुल डिजिटल भुगतानों का 85% और वैश्विक डिजिटल लेनदेन का लगभग आधा हिस्सा बनाता है।
- The rollout in Qatar is a collaboration between NPCI International Payments Ltd (NIPL), Qatar National Bank (QNB), and Japanese payment gateway NETSTARS.
- क़तर में यह लॉन्च एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL), क़तर नेशनल बैंक (QNB) और जापानी पेमेंट गेटवे NETSTARS के सहयोग से किया गया है।

Ques: According to the World Bank, what is India's GDP growth estimate for FY26?

विश्व बैंक के अनुसार, भारत की FY26 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान कितना है?

- A) 6.3%
- B) 6.5%
- C) 6.7%
- D) 6.8%
- E) 6.9%

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The World Bank has raised India's FY26 GDP growth forecast from 6.3% to 6.5%, backed by strong domestic demand and rural growth.
- विश्व बैंक ने भारत की FY26 GDP ग्रोथ अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है, जिसकी वजह मजबूत घरेलू मांग और ग्रामीण विकास बताई गई है।
- However, the FY27 outlook has been lowered to 6.3% due to potential impacts from higher US tariffs on Indian exports.
- हालांकि, FY27 का अनुमान घटाकर 6.3% किया गया है क्योंकि अमेरिका द्वारा भारत के उत्पादों पर बढ़ाए गए टैरिफ का असर पड़ेगा।

Ques: Which insurance company launched the "Health Alpha" plan — the first retail health insurance product introduced after GST reforms?

किस बीमा कंपनी ने "हेल्थ अल्फा" योजना लॉन्च की — जो जीएसटी सुधारों के बाद पेश किया गया पहला रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस उत्पाद है?

- A. HDFC ERGO General Insurance / एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस
- B. ICICI Lombard General Insurance / आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस
- C. SBI General Insurance / एसबीआई जनरल इंश्योरेंस
- D. Bajaj Allianz General Insurance / बजाज एलियांज़ जनरल इंश्योरेंस
- E. New India Assurance / न्यू इंडिया एश्योरेंस

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- SBI General Insurance launched Health Alpha, India's first retail health insurance product introduced after GST reforms.
- एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने हेल्थ अल्फा लॉन्च किया, जो जीएसटी सुधारों के बाद पेश किया गया पहला रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस उत्पाद है।
- The plan is fully customisable with over 50 coverage options, offering sum insured from ₹5 lakh to unlimited cover, and allows add-on benefits tailored to customers' lifestyle and budget.
- यह योजना पूरी तरह से अनुकूलन योग्य है, जिसमें 50 से अधिक कवरेज विकल्प, ₹5 लाख से असीमित बीमित राशि और ग्राहकों की जीवनशैली और बजट के अनुसार अतिरिक्त लाभ चुनने की सुविधा उपलब्ध है।

Ques: Which company, in collaboration with YES Bank, launched India's first biometric card authentication system compliant with RBI's 2025 guidelines?
YES बैंक के सहयोग से RBI की 2025 दिशानिर्देशों के अनुरूप भारत की पहली बायोमेट्रिक कार्ड प्रमाणीकरण प्रणाली किस कंपनी ने शुरू की?

- A. Paytm / पेटीएम
- B. Razorpay / रेज़रपे
- C. PhonePe / फोनपे
- D. Google Pay / गूगल पे
- E. BharatPe / भारतपे

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Razorpay, in collaboration with YES Bank, launched India's first biometric card authentication system compliant with the Reserve Bank of India's (RBI) 2025 guidelines.
- रेज़रपे ने YES बैंक के सहयोग से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की 2025 दिशानिर्देशों के अनुरूप भारत की पहली बायोमेट्रिक कार्ड प्रमाणीकरण प्रणाली शुरू की।

- This system enables online card payments through facial recognition, replacing traditional two-factor authentication methods that relied on PINs and SMS OTPs.
- यह प्रणाली पारंपरिक दोकार-क प्रमाणीकरण विधियों जैसे PIN और SMS OTP की जगह चेहरे की पहचान (फेशियल रिकग्निशन) के माध्यम से ऑनलाइन कार्ड भुगतान को प्रमाणित करने की अनुमति देती है।
- It can process up to 10,000 transactions per second, reducing OTP-related errors and improving the overall payment experience.
- यह प्रणाली प्रति सेकंड 10,000 लेनदेन संसाधित करने में सक्षम है, जिससे OTP से संबंधित त्रुटियाँ कम होती हैं और भुगतान अनुभव अधिक सुगम बनता है।

About YES Bank :

- Established : 2004
- HQ : Mumbai, Maharashtra
- MD & CEO : Prashant Kumar
- Chairman : Rama Subramaniam Gandhi
- Tagline : Experience our Expertise

Ques: Which Indian stock-trading platform recently achieved unicorn status after a \$120 million funding round led by Hornbill Capital and MUFG?

किस भारतीय स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने हाल ही में-Hornbill Capital और MUFG द्वारा संचालित \$120 मिलियन फंडिंग राउंड के बाद यूनिकॉर्न दर्जा प्राप्त किया है?

- A. Groww / ग्रो
- B. Zerodha / ज़ेरोधा
- C. Angel One / एंजल वन
- D. Dhan / धन
- E. Upstox / अपस्टॉक्स

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Dhan, a stock-trading platform under Raise Financial Services, became a unicorn after raising \$120 million in a round led by Hornbill Capital and Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG).
- Dhan, जो Raise Financial Services के अंतर्गत आता है, ने Hornbill Capital और MUFG के नेतृत्व में \$120 मिलियन जुटाकर यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया।
- The investment values Dhan at \$1.2 billion (₹10,000 crore), making it one of India's newest fintech unicorns.
- इस निवेश से Dhan का मूल्यांकन लगभग \$1.2 बिलियन (₹10,000 करोड़) हो गया, जिससे यह भारत के नवीनतम फिनटेक यूनिकॉर्न में शामिल हो गया।
- Dhan competes with top trading platforms like Groww, Zerodha, and Angel One, and had 0.9 million active traders as of August 2025.
- Dhan, Groww, Zerodha और Angel One जैसे प्रमुख ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से प्रतिस्पर्धा करता है, और अगस्त 2025 तक इसके पास 0.9 मिलियन सक्रिय ट्रेडर्स थे।

Ques: What is the revised world goods trade growth forecast for 2025 as per WTO?

WTO के अनुसार 2025 के लिए विश्व वस्तु व्यापार वृद्धि का नया अनुमान क्या है?

- A. 0.9%
- B. 1.8%
- C. 2.4%
- D. 4.6%
- E. 0.5%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The World Trade Organization (WTO) increased the global goods trade growth forecast for 2025 to 2.4%, citing AI-driven demand and frontloading of US imports as major reasons.
- WTO ने AI-आधारित उत्पादों की बढ़ती मांग और अमेरिका द्वारा टैरिफ से बचने के लिए अग्रिम आयात को कारण बताते हुए 2025 के लिए वस्तु व्यापार वृद्धि का अनुमान 2.4% कर दिया।

- Meanwhile, the 2026 projection has been revised downward to 0.5%, showing the expected slowdown after the tariff adjustments.
- वहीं, 2026 का अनुमान घटाकर 0.5% कर दिया गया है, जो टैरिफ समायोजन के बाद संभावित मंदी को दर्शाता है।

Ques: Which co-operative bank launched India's first youth-focused digital banking app 'Cosmos Galgal'?

भारत का पहला युवा केंद्रित डिजिटल बैंकिंग ऐप-'Cosmos Galgal' किस सहकारी बैंक द्वारा लॉन्च किया गया?

- A. Saraswat Co-operative Bank / सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक-
- B. Cosmos Co-operative Bank / कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक-
- C. Shamrao Vithal Co-operative Bank / शामराव विठ्ठल कोऑपरेटिव बैंक-
- D. Abhyudaya Co-operative Bank / अभ्युदया कोऑपरेटिव बैंक-
- E. Punjab & Maharashtra Co-operative Bank / पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक-

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Cosmos Co-operative Bank, in partnership with Umunthu System Private Limited, launched 'Cosmos Galgal', India's first youth-focused digital banking app.
- कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक ने- उमुन्थु सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में भारत का पहला युवाकेंद्रित डिजिटल बैंकिंग ऐप- 'Cosmos Galgal' लॉन्च किया।
- The app offers integrated video KYC, enabling users to open zero-balance savings accounts within 15 minutes from anywhere.
- यह ऐप वीडियो KYC सुविधा के साथ उपयोगकर्ताओं को कहीं से भी 15 मिनट में ज़ीरो-बैलेंस सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा प्रदान करता है।
- Established in 1906, Cosmos Co-operative Bank is headquartered at Cosmos Tower, Pune, Maharashtra.
- 1906 में स्थापित, कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक का मुख्यालय- कॉसमॉस टॉवर, पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है।
- It is among the first co-operative banks in India to implement Core Banking Solution (CBS).

- यह भारत के पहले सहकारी बैंकों में से एक है जिसने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) लागू किया।

Ques: What is the maximum compensation proposed by RBI that the banking ombudsman can award to aggrieved bank customers for consequential loss?
बैंकों के ग्राहकों को हुई परिणामी हानि के लिए बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी जा सकने वाली अधिकतम क्षतिपूर्ति राशि क्या प्रस्तावित की गई है?

- A. ₹10 lakh
- B. ₹20 lakh
- C. ₹25 lakh
- D. ₹30 lakh
- E. ₹35 lakh

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India has proposed that the banking ombudsman may compensate aggrieved customers up to ₹30 lakh for any consequential loss suffered.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रस्ताव दिया है कि बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों को हुई परिणामी हानि के लिए अधिकतम ₹30 लाख तक का मुआवजा दे सकता है।
- Additionally, the ombudsman may award up to ₹3 lakh for harassment, mental agony, or time spent in pursuing the grievance.
- इसके अलावा, शिकायत के निपटारे में हुई मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न या समय की हानि के लिए लोकपाल अधिकतम ₹3 लाख तक का मुआवजा दे सकता है।
- Customers of state and central cooperative banks can approach the ombudsman structure from November 1, 2025.
- राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों के ग्राहक 1 नवंबर 2025 से बैंकिंग लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
- If banks fail to respond within 30 days, customers can escalate their complaints to the RBI.
- यदि बैंक 30 दिनों में जवाब नहीं देते, तो ग्राहक अपनी शिकायतें RBI तक बढ़ा सकते हैं।

Ques: ICICI Bank has launched the Corporate Sapphire Forex Card in collaboration with which global payment network?

आईसीआईसीआई बैंक ने कॉर्पोरेट सैफायरो फॉरेक्स कार्ड किस वैश्विक भुगतान नेटवर्क के सहयोग से लॉन्च किया है?

- A. Mastercard / मास्टरकार्ड
- B. Visa / वीज़ा
- C. American Express / अमेरिकन एक्सप्रेस
- D. RuPay / रुपये
- E. Discover / डिस्कवर

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- ICICI Bank has partnered with Visa to launch the Corporate Sapphire Forex Card — the first prepaid card by any Asian bank powered by Visa Infinite, designed for entrepreneurs and corporate travelers.
- आईसीआईसीआई बैंक ने वीज़ा के साथ मिलकर कॉर्पोरेट सैफायरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है — जो किसी भी एशियाई बैंक द्वारा वीज़ा इंफिनिट द्वारा संचालित पहला प्रीपेड कार्ड है, जिसे उद्यमियों और कॉर्पोरेट यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है।
- The card offers premium benefits like airport lounge access, travel insurance, global customer assistance, multi-currency loading, and enhanced security for international transactions.
- यह कार्ड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, ट्रैवल इंश्योरेंस, ग्लोबल कस्टमर असिस्टेंस, मल्टी-करेंसी लोडिंग और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए उन्नत सुरक्षा जैसी प्रीमियम सुविधाएँ प्रदान करता है।